कृषि लोक
कृषि एवं किसान के लिए ई-पत्रिका
http://www.rdagriculture.in
e-ISSN No. 2583-0937
कृषि लोक, खंड 02 (03): 127-130, 2022

भारतीय कृषि में सुधार

प्रवीण कुमार , रिषभ कुमार दीदावत

भा. कृ. अ. प. - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली 110012

*संबंधित लेखक: parveenkumar2866@gmail.com

भारत में कृषि नीतियों को संस्थानों की एक जटिल प्रणाली द्वारा डिजाइन और कार्यान्वित किया जाता है। कृषि के कई पहलुओं के लिए राज्यों की संवैधानिक जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र सरकार नीति के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करके और राज्य स्तर पर कार्यान्वयन के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारी एजेंसियों का किसान की आजीविका के सभी पहलुओं पर एक कहना है-नवीनतम निष्कर्षों में विभिन्न केंद्रीय और राज्य मंत्रालय और एजेंसियां शामिल हैं जो ग्रामीण संपत्ति के अधिकारों, भूमि उपयोग और भूमि की सीमा की देख रेख करती हैं, कमोडिटी की कीमतें, इनपुट सब्सिडी और कर, बुनियादी ढांचा, उत्पादन, ऋण, विपणन और खरीद, सार्वजनिक वितरण, अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार सेवाएं; व्यापार नीती; कृषि-व्यवसाय और अनुसंधान-सूची जारी है।

कृषि, आधुनिक शब्दावली जो खेती से लेकर पशुपालन तक की आर्थिक गतिविधियों को सामान्य बनाती है, औद्योगिक क्रांति का मार्ग

e-ISSN No. 2583-0937

प्रशस्त करने से पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था का स्तंभ रही है। जैसा कि दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं के विकास के माध्यम से देखा जाता है, विकास कृषि को अपनाने वाले लोगों के साथ शुरू होता है, और प्राथमिक क्षेत्र आमतौर पर सबसे बड़ा नियोक्ता बन जाता है। कृषि, जो शुरुआती समय में, निर्वाह के इरादे से शुरू हुई, प्रभावी रूप से एक वाणिज्यिक बाज़ार में परिवर्तित हो गई, जिसके परिणामस्वरूप अच्छी तरह से विकसित विपणन प्रणालियों का निर्माण हुआ, जिसने न केवल "**दोहरा संयोग**" के विचार को समाप्त कर दिया। वस्तु विनिमय), लेकिन पैसे के रूप में एक शक्तिशाली विनिमय तंत्र की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। भारत में, हरित क्रांति (जिसने गेहूँ और धान के उत्पादन में तेजी आई) से पहले, 1950 के दशक के अंत और 60 के दशक की शुरुआत में, कृषि देश की बढ़ती आबादी को बनाए रखने में असमर्थ थी, और इसे प्राप्त करने के लिए गंभीर सुधारों से गुजरना पड़ा। आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली। इस प्रकार हरित क्रांति के हिस्से के रूप में तकनीकी प्रगति हुई, जिसने सिंचाई सुविधाओं में सुधार किया, कृषि को बदलने के लिए उच्च उपज वाली किस्म (एचवाईवी) बीजों को पेश किया जिसे हम जानते हैं।प्रणाली में कुछ दोषों को ठीक करने के लिए ऐसे सुधारों की आवश्यकता होती है, जो अपरिहार्य हैं, और सिस्टम की कार्यक्षमता के निरंतर रखरखाव के लिए आवश्यक हैं। भारत में कृषि न केवल प्राकृतिक स्थलाकृति और जलवायु के मामले में, बल्कि भूमि वितरण के परिदृश्य में भी अद्वितीय है। एक भारतीय किसान की औसत भूमि जोत एक हेक्टेयर (कृषि जनगणना 2015-16) से ठीक ऊपर है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में, औसत कृषि भूमि का क्षेत्रफल 440 हेक्टेयर है। इस तरह की अल्प भूमि जोत किसानों की उत्पादकता में बाधा डालती है, क्योंकि उत्पादित फसल का एक बड़ा हिस्सा बहुत आवश्यक निर्वाह के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे किसानों का समग्र लाभ सीमित हो जाता है।इसलिए, कोई भी कृषि सुधार मुख्य रूप से सीमांत / छोटे किसानों के इन समूहों को लक्षित करता है जो आम तौर पर जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं।

मौजूदा व्यवस्था के साथ उभरे मुद्दे

राज्यों में अलग-अलग पैदावार: हरित क्रांति के पांच दशकों के बाद भी देश के बाकी हिस्सों में हरित क्रांति वाले राज्यों और कृषि जिलों के बीच चावल और गेहूं की पैदावार में बड़ा अंतर है। इसके अलावा, पंजाब और हरियाणा के बाहर उगाए गए चावल और गेहूं जिलों में उपज भिन्नता या जोखिम के उच्च स्तर को प्रदर्शित करना जारी रखते हैं।

अवसंरचनात्मक विकास का अभाव: जिलों में सिंचाई, सड़क, बिजली आदि सामान्य वस्तुओं के प्रावधान में भारी असमानता है।

कृषि भूमि, फसलों और आदानों के लिए अच्छी तरह से काम करने वाले बाजारों की अनुपस्थिति के साथ, धीमी गति से श्रम सुधार और शिक्षा की खराब गुणवत्ता ने कृषि जिलों के भीतर और पूरे संसाधन गतिशीलता को कम कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने उत्पादकता बढ़ाने और जिलों में उपज की भिन्नता को कम करने के लिए आवश्यक विचारों और प्रौद्योगिकी की गतिशीलता को सीमित कर दिया है।

प्रभावी विकेंद्रीकृत का अभाव: एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली का वास्तविक वादा - प्रयोग करने का, एक दूसरे से सीखने का, और सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतियों को अपनाने का - काफी हद तक विफल रहा है। इसके बजाय, आजादी के बाद से भारतीय कृषि अत्यधिक खंडित रही है।

प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास: राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न इनपुट सब्सिडी और न्यूनतम मूल्य गारंटी खरीद योजनाओं ने उत्पादकता के समग्र स्तर और कृषि में जोखिम को खराब करने, जल संसाधनों, मिट्टी, स्वास्थ्य, और जलवायु।

कृषि क्षेत्र की कीमत पर खाद्य सुरक्षा: इसका परिणाम केंद्र और राज्य सरकार दोनों एजेंसियों द्वारा मनमाने और परस्पर विरोधी नीतिगत हस्तक्षेपों का दम घुटने वाला मिश्रण

e-ISSN No. 2583-0937

रहा है। विडंबना यह है कि "**खाद्य सुरक्षा**" एक कृषि क्षेत्र की कीमत पर लाई गई है जो सभी हितधारकों-किसानों, घरों, उपभोक्ताओं, व्यापारियों, फर्मों और राज्य को पकड़ती है - व्यक्तिगत कल्याण के निम्न स्तर और समग्र जोखिम के उच्च स्तर के साथ।

कृषि मे सुधार के समाधान

आय को अधिकतम करना, जोखिम को कम करना: तीन कृषि कानून आर्थिक सुधारों के व्यापक सेट का केवल एक हिस्सा हैं जिनकी भारतीय कृषि को स्थिर करने के लिए आवश्यकता होगी। इन सुधारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना होना चाहिए जो भारतीय कृषि में जोखिम के समग्र स्तर को कम करते हुए कृषि परिवारों को अपनी आय को अधिकतम करने की अनुमति दें।

उदारीकृत खेती: किसानों को अपने खेतों के लिए संसाधनों, भूमि, आदानों, प्रौद्योगिकी और संगठनात्मक रूपों के सर्वोत्तम मिश्रण का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र किया जाना चाहिए। राज्य ने बहुत लंबे समय से कृषि परिवारों को उत्पादन, विपणन और वितरण योजनाओं के अधीन किया है। किसानों को, गैर-कृषि क्षेत्र के उद्यमियों की तरह, उन्हें अपनी शर्तों पर कृषि में प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति दी जानी चाहिए और वे जिसे चाहें, अनुबंधित कर सकते हैं।

कृषि संस्थानों और शासन प्रणालियों में सुधार: प्रमुख नीति क्षेत्रों को एक छतरी के नीचे लाकर केंद्रीय स्तर पर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करना।

विकेंद्रीकृत प्रणाली की तरह: देश भर में किसानों और कृषि संसाधनों की अधिक गतिशीलता की अनुमति देने वाले मौलिक सुधारों की आवश्यकता है। एक वास्तविक विकेन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था में, असम के एक किसान को "**पंजाब मॉडल**" से उतना ही लाभ मिलना चाहिए जितना कि पंजाब के किसानों को, और इसके विपरीत।

बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना

कृषि में अल्प-रोजगार/प्रच्छन्न बेरोजगारी एक और बड़ी समस्या है जो भारत में मौजूद है और इसका आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यह केवल एक घटना है जहां किसी विशेष कार्य में आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति कम आर्थिक उत्पादन होता है। ऐसे मामले में, "उन अतिरिक्त कर्मचारियों" को हटाने से कुल उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। यह घटना मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र में मौजूद है, और ग्रामीण भारत (कृषि गतिविधियों का केंद्र) में रोजगार के अवसरों की कमी और कृषि की मौसमी प्रकृति के कारण भी है। भारत में बेरोजगारी को कम करने के लिए, हम लोगों को इसी तरह के मौसमी काम प्रदान करने और उनके पेशे को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की योजना बना सकते हैं।बस, हमें 2005 में शुरू किए गए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के समान कानूनों को पेश करना होगा, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों के लिए गारंटीकृत काम प्रदान करना है। दूसरे शब्दों में, यह अल्प-रोजगार वालों को रोजगार प्रदान करता है। मनरेगा न केवल बेरोजगार युवाओं को उचित मजदूरी (राज्यों में औसत दैनिक मजदूरी: 233.3 रुपये) अर्जित करने में मदद करता है, यह भारतीय आबादी को दायित्व के बजाय एक संपत्ति के रूप में मानने की संभावना भी पैदा करता है।ऐसी नीतियां बेरोजगार युवाओं को अन्य व्यवसायों से परिचित होने और आर्थिक विकास के संदर्भ में उनकी वास्तविक क्षमता का पता लगाने के लिए एक आधार प्रदान करती हैं।हमारे कार्यबल के और अधिक शोषण को रोकने के लिए, भारत की ग्रामीण आबादी को स्थायी रोजगार प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली अतिरिक्त नीतियां लानी होंगी। बेरोजगारी के कारण, भारत में कृषि की विकास दर भी कम है (विकास दर केवल 4.5 को छूती है) %,

e-ISSN No. 2583-0937

एक दशक की लंबी अवलोकन अवधि में), इसमें "संलग्न" कार्यबल की मात्रा को देखते हुए। इसलिए, यह निहित किया जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अल्प-रोजगार एक बचाव का रास्ता है, और इसका उन्मूलन प्राथमिक क्षेत्र के लिए और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण होगा। 1960 के दशक में भारत की स्थिति के विपरीत, भारत खाद्य उपलब्धता और उत्पादकता के मामले में आत्मनिर्भर है, इसलिए हरित क्रांति 2.0 न केवल बेरोजगारी को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, बल्कि बेहतर आर्थिक परिणामों के लिए काम करने का भी लक्ष्य रखेगा।

नीतियों में सुधार करना

समाधानों के नए सेट में वर्तमान कृषि वाणिज्यिक विपणन प्रणाली का विकास शामिल हो सकता है, और प्रमुख नकदी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के लिए एक समृद्ध और विविध बाजार बना सकता है। इस तरह हम निश्चित रूप से अधिक किसानों को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें उन फसलों को भी लेने के लिए एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान कर सकते हैं।इसके अतिरिक्त, किसानों को अधिक फलने-फूलने के लिए ग्रामीण भारत में सहकारी समितियों की स्थापना की भी आवश्यकता है, क्योंकि सस्ते ऋण उन्हें उन्नत उपकरणों में निवेश करने में मदद कर सकते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक अच्छी तरह से विकसित सिंचाई प्रणाली किसानों की वर्षा पर निर्भरता को खत्म कर सकती है, और उन्हें एक ही कृषि वर्ष में अधिक फसल उगाने में मदद कर सकती है। किसानों के आर्थिक शोषण को रोकने के लिए 1960 के दशक में शुरू की गई एक अन्य नीति, एमएसपी में सुधार किया जाना है। एक मध्यस्थ ग्राहक के रूप में सरकार के हस्तक्षेप ने कृषि फसलों की कीमतों का संतुलन सुनिश्चित किया, और एमएसपी ने सुनिश्चित किया कि किसानों को उनकी फसल से पर्याप्त लाभ मिले। इस नीति का दर्शन बहुत उपयुक्त है, लेकिन अभी जिस पर काम करने की जरूरत है वह है ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा 2013 में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग 22% किसानों को रबी और खरीफ सीजन की फसलों के लिए एमएसपी प्रदान किए जाने के बारे में पता था, जो कि कार्यान्वयन में सुधार की एक बड़ी गुंजाइश का सुझाव देता है। नीति के। हालांकि यह प्रतिशत समय के साथ बढ़ा हो सकता है, एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अधिक कृषि व्यवसायियों को कानूनों के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

भारत का कृषि-खाद्य क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जो कई चुनौतियों और कई अवसरों का सामना कर रहा है। यदि आवश्यक सुधारों को लागू किया जाता है, तो भारत को अपनी विशाल आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा में सुधार करने, अपने लाखों छोटे धारकों के जीवन की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने, गंभीर संसाधनों और जलवायु दबावों को दूर करने में मदद मिलेगी, साथ ही स्थायी उत्पादकता वृद्धि पैदा करने और एक आधुनिक, कुशल और लचीला कृषि का निर्माण करने में मदद मिलेगी। खाद्य प्रणाली जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास और नौकरियों में योगदान दे सकती है। श्री एम.एस. स्वामीनाथन की तरह, जिन्हें 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है, हमें भारत में कृषि में बेरोजगारी और अन्य मौजूदा समस्याओं को दूर करने के लिए और अधिक महत्वाकांक्षी वैज्ञानिकों की आवश्यकता है।